ग्रभी ऐसा भी है कि हमारी जो मैन पावर है, मनुष्य बल है उसका उपयोग, उसका यूज ग्रच्छी तरह से कैसे करें। इस पर हमारे देश की ग्रर्थव्यवस्था निर्भर है। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं जरूर कहता हूं कि ग्रादिवासी क्षेत्रों में रोजगार देने के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। ग्रौर उसको प्रोयोरिटी देनी चाहिए। मैं जरूर उम्मीद रखता हूं कि हमारे जो कृषि मंत्री जाखड़ साहब हैं वे इस पर जरूर ध्यान देंगे।

5.00 PM दूसरी बात जो माननीय सरला माहेश्वरी जी ने उटाई है कि भूख से संबंधित रोगों से लोगों के इलाज के लिए पर्याप्त राहत उपाय शुरू किये जायें, यह भी काफी ग्रच्छी बात उन्होंने उठाई है। भूख से पीड़ित लोगों में जो रोग होते हैं, जो डिजीजिज होती हैं, उनका भी संशोधन होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में बहुत सारे रोग ऐसे हैं, जो डेफिशेंसी ग्राफ न्युट्रिएंट्स की वजह से होते हैं, ग्रच्छी तरह से खाने के लिए न्यूटिएंट नहीं मिलते, ग्रच्छी तरह से उनकी व्यवस्था नहीं होती, सारी उनकी हाईजीनिक कंडिशंस नहीं होतीं, इसकी वजह से भी काफी बीमारियां होती हैं। (समय की घंटी) तो उसके संबंध में भी हमें काफी ग्रच्छी तरह से सोचना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Private Members' business is over for the day. If you want, you continue your speech next time.

Now, I have the second Supplementary List of Business before me. Paper to fee laid on the Table—Shri Shantaram Potdukhe.

## PAPER LAID ON THE TABLE— Contd.

### Notification of the Ministry of Financs Department of Revenue)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE: Madam, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification G.S.R. No. 679(E) dated the 17th July 1992, exempting persons who have been resident outside India from the obligation of surrender of their foreign currency assets held abroad when they return to India together with an Explanatory Memorandum thereon. [Placed in Library. *See* No. LT-/92.]

## CLARIFICATIONS ON STATEMENT RE. DERAHJVfENT OF 8033 AHMEDABAD-HOWRAH EXPRESS ON BADNERA-WARDHA SECTION OF CENTRAY RAOLWAY

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Now, clarifications on the statement by the Minister of Railways. Shri V. Narayanasamy, ...Not here. Shri Ram Naresh Yadav.

**श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) :** महोदया, जो रेलवे की यह घटना घटी, वह बहुत ही दुखद ग्रौर चिंतनीय रही ग्रौर जो लोग इसमें मरे, उससे इस पूरे सदन की समवेदना है ग्रौर साथ ही साथ यह है कि ग्राये दिन ऐसा देखा जाता है कि रेलवे की कहीं न कहीं घटनायें हुग्रा करती हें। उसमें जानें जाती हैं। उसके बाद फिर बयान हम देते है ग्रौर बयान देने के बाद फिर वहां से मामला ठंडा पड़ जाता है।

ऐसी स्थिति में जो यहां पर घटना घटी है, पैरा दो में जिस तरह कि जो सरकार को रिपोर्ट मिली ग्रौर उसके बाद माननीय मंत्री जी गये, दूसरे ग्रधिकारी भी गये, मौके पर जाकर के सारी चीजों को देखा। तो वहां पर जो ग्राया है, वह यह है कि फिश प्लेट्स, नट-बोल्ट्स ग्रप ग्रौर डाउन ट्रैक के सब हटा दिये गये थे ग्रौर फिश प्लेट्स हटा दी गई थीं, सब चीजें कुछ इधर-उधर बिखरी पड़ी थीं।

[श्री राम नरेश यादव]

मैं जानना चाहता हूं कि वैसे तो आप, जांच करवा रहे हैं, लेकिन आजकल जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, एक्सप्लोसिव सब्स्टांस का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा कोई षडयंत्र नहीं है कि कहीं इस रेल की पटरी को उड़ाने की साजिश तो आतंकवादियों द्वारा नहीं की गई।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी का उधर भी ध्यान गया है, और यदि नहीं गया, तो इस प्रश्न पर भी जांच करवाने का काम करें इस बिंदु पर कि क्या यह भी संभावना है कि नहीं, क्योंकि आजकल जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां तेज हो रही हैं सारी जगह, उससे जरूर यह संभावना बनती है कि हो सकता है कि इस घटना में भी इस तरह से उन लोगों का हाथ हो और सरकार को बदनाम करने के लिए और डी-स्टेबिलाईज करने के लिए इस तरह की सारी साजिशें रची जा रही हों। इस बिंदु पर भी जानकारी करने का काम करें।

दूसरा प्रश्न मैं यह उठाना चाहता हूं कि इसमें जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, जांच बैठती है और रिपोर्ट आती है, लेकिन उस पर कार्यवाही क्या होती है, क्योंकि हम तो बयान दे देते हैं, लोग प्रश्न पूछ लेते हैं। मंत्री जी जवाब भी दे देते हैं, फिर इसके बाद जो जांच की रिपोर्टस आती हैं, उन पर सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गई, या रेलवे विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इस बारे में सदन को कोई जानकारी नहीं पहुंचती। इसलिए मैं जानना चाहता हूं पिछले संदर्भ में, जिस तरह से घटनायें घटी, बहुत सी जांच बिठाई गई, रिपोर्टस आईं। क्या उसको ध्यान में रखते हुए इस रेलवे लाईन की सुरक्षा के लिए भी क्या रेल विभाग से ऐसी कोई व्यवस्था की गई थी ताकि रेल की पटरियों की देखरेख हो सके, कोई इस तरह की बात न हो सके?

तीसरा प्रश्न यह है—एक तो प्रश्न यह खड़ा होता है इसमें, जैसे रेल की पटरी है, रेलवे विभाग की तरफ से उसकी सर्वेलेंस भी होती है, बराबर उसके किनारे पटरियों पर प्रशासन व्यवस्था भी होती है।

मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस रेलवे लाईन पर क्या सरकार की तरफ से कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था पहले की गई थी, और अगर नहीं की गई थी, तो क्यों नहीं की गई थी?

क्या पैट्रोलिंग की व्यवस्था है कि नहीं है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और क्या आगे इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे लाईनों की पैट्रोलिंग की विशेष व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे, यह हम जानना चाहते हैं।

इसके बाद जिस तरह से अभी तक— मेरा तो सचमुच में कहना यह है कि जहां पर यह घटना घटी है वहां से लेकर अगला स्टेशन और बीच का स्टेशन, उसके बीच के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, कर्मचारी तो बेचारे छोटे होते हैं वे क्या करें, अधिकारी ही दोषी हैं, क्योंकि लगता है कि अधिकारियों ने जांच-पड़ताल करने में और उसकी देखरेख करने में कोई लापरवाही बरती है। क्योंकि जब पिछली बार भी कई जगह पर एक ही लाईन पर घटना घटी तो हम लोगों ने सवाल उठाया था कि सरकार की तरफ से अब रेल पटरियों की रखवाली के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। अगर यह व्यवस्था नहीं की गई तो वहां के जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है, यह मैं जानना चाहता हूं? क्योंकि कितनी बड़ी घटना हो जाए, लोग मर जायें, नुकसान हो जाए, काल में आयें और हम लोग यहां बैठ करके चिंता व्यक्त करें और पूरे देश के लोग समझें एक ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम गाड़ी पर क्यों चलें, इस तरह किसी न किसी आदमी को मजबूर हो कर चलना ही पड़ता है, इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या

सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ? साथ ही साथ, जो लोग मरे भी है, ठीक है सरकार के कुछ नार्म्ज बने हुए हैं उसके आधार पर उन लोगों को दो लाख और कुछ और इस तरह की व्यवस्था करती है, लेकिन विशेष रूप से सवाल यह आता है कि बेचारे निर्दोष लोग जो मर गए उनका तो कोई दोष नहीं था, तो ऐसे लोगों के परिवारों के लिए भी सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, मुख्य बात यह है क्योंकि सहानुभूति के आधार पर भी और वैसे भी उस आधार पर क्या व्यवस्था करने जा रही है, यह जानना चाहता हूं ?

आखिरी बात यह है कि भविष्य में रेलवे विभाग इतना बड़ा है एशिया का इतना बड़ा और इतने बड़े उद्यम में अगर इस तरह की बात होती हैं तो लोगों को थोड़ा संदेह पैदा होता है, इस लिए इसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में सुरक्षात्मक व्यवस्था के दृष्टिकोण से क्या-क्या उठाने की योजना इस सरकार ने बनाई है, वह भी हम जानना चाहते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ); Shri Anand Prakash Gautaro cot present

Shri Vithalbhai Patel.

SHRI V. NARAYANASAMY Pondicherry) : Madam, my name?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): At the end I will call you. I called you. You were not present then.

SHRI V. NARAYANASAMY; Madam. will you call the first name at the end?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): No, no. I called your name: Your were not present. You were absent. You were not present. That is why I am saying that I will call you at the end.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL (Gujarat): Madam, the Ahmedabad-Howrah Express is a long-distance train, but, unfortunately, its second-class coaches are very old_ The life of the coaches has already expired. Such type of coaches should not be used in long-distance trains. I have written a letter to the hon. Railway Minister about the pitiable condition of this Ahmedabad-Howrah Express train. There is now after. The coaches are also very old. Their life has already expired They are poorly maintained. The Ministers reply what the bureaucrats dictate them. They them-' selves do not enquire. When we Members of Parliament write to you that this is the condition of this particular train, you should believe us because we know it, we have personally seen it. I have travelled by it. So, I am saying this.

Number two, he has said about the compensation Let me remind him that the procedure is so bad that it is very difficult for the victims to get compensation. I reminded him about the Karnataka Express accident which had taken place more than two-and-a-half years or three years ago. I know that one victim has not got the compensation so far. Mr. Railway Minister, the Karnataka Express accident took place three years back Two children, minor children are there, whose mother died. Their grandmother is looking after them. I myself and two other MPs wrote to the Railway Minister to pay com-,j, pensation to the old lady, the grand-, mother. Yet she has not got it. She has to Bring a certificate from the court. The old lady, uneducated lady I has been asked to bring a certificate from the court. She went to Lucknow because the tribunal was at Lucknow. At Lucknow she approached some lawyer. The lawyer demanded] Rs. 20,000. This lady says, "I do not have Rs. 200. How can I pay Rs. 20,000?" In such cases, Mr. Minister, some way you have to find out. Give legal aid to the victim and see that the case is disposed of. Even after three years of the railway accident if the old lady does not get the compensation, then, what is the use of the com. pensation?

[Shri Vithalbhai M. Patel]

It is your duty, not of the relatives of the victims, to find out the way to get the compensation. There may be a number of cases where the compensation might not have been paid yet, but this case we know, because it came to us. So, my request to the hon. Minister is that the compensation should be paid promptly to the next of kin of the victims. Secondly, coaches whose life has expired, should be removed from the Ahmedabad-Howrah train

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** (उत्तर प्रदेश) : महोदया, इस दुर्घटना के संबंध में मुझे कुछ संदेह हो रहा है और यह बयान में भी कहा गया है कि शायद यह जानबूझकर की गयी दुर्घटना है यानी सैबोटेज की इस में संभावना है और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को पकड़ा गया है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय का क्या संदेह है ? इस सैबोटेज के क्या कारण हो सकते हैं ? क्या मजदूरों और कर्मचारियों की कोई मांगें ऐसी हैं अथवा ये लुटेरे हैं या पंजाब के आतंकवादियों से संबंधित कोई व्यक्ति है। मेरा आग्रह यह होगा कि इस सैबोटेज में टेरेरिज्म या टेरेरिस्ट्स का कोई हाथ है या नहीं, इसे गहराई से देखा जाना चाहिए। इसलिए केवल रेलवे के जो लोग हैं, वह इंक्वायरी करें यह पर्याप्त नहीं है। रेलवे के लोग या रेलवे सेफ्टी सर्किल तो इंक्वायर केवल इस बात की कर सकती है कि क्या किसी कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी से हटकर काम किया है, लेकिन इसका जो वास्तविक उद्देश्य है कि यह क्यों किया गया है, यह रेलवे डिपार्टमेंट खोज नहीं कर सकता। आप आफिसिअली चाहें या न चाहें लेकिन मेरा कहना यह है कि सी०बी०आई० अथवा पुलिस के किन्हीं अधिकारियों के माध्यम से यह जांच कराई जानी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि इसमें आतंकवादियों का कहीं-न-कहीं हाथ हो। मेरा यह आग्रह नहीं है कि आप यह इक्वायरी की रिपोर्ट जनता के सामने रखें। अगर रख देंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन सरकार को, विभाग को यह जानकारी मिल जाय कि वास्तव में इसमें किन्हीं अन्य कारणों का हाथ नहीं है जैसाकि मैंने आतंकवादियों का कहा है।

दूसरे, क्या ऐसे भी कुछ प्रमाण पाए गए हैं कि जो लोग रेलवे ट्रैक की देख-भाल करते हैं जिसमें कि आपके परमानेंट वे इंस्पेक्टर (पी.डब्लू.आई.) भी होते हैं और उसके साथ में गेंगमेन होते हैं तो इनमें से किन-किन की जिम्मेदारी थी ? वह जिम्मेदारी फिक्स करने की क्या कार्यवाही की गई है या नहीं की गई है ? अगर नहीं की गयी है तो की जानी चाहिए, खास तौर से जो भी पी०डब्लू० आई० है उसकी जिम्मेदारी है। फिर आपने कम्पेनसेशन की बात कही है और कहा है कि कम्पेनसेशन 16 हजार से 1 लाख 80 हजार तक हो सकता है। तो वास्तव में कम्पेनसेशन कितने लोगों को और कितना-कितना दिया गया है या दिया जाने वाला है ? मेरा विनम्र आग्रह है कि अगर आपने अभी अभी यह फिक्स नहीं किया है तो एक-एक आदमी के लिए फिक्स करिए और जल्दी-से-जल्दी उनको पैसे की अदायगी की जानी चाहिए।

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस दुखद रेलवे हादसे पर गहरी चिंता व्यक्त करती हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति भेजती हूं।

महोदया, मुझे अफसोस एक बात का और भी है कि ये रेलवे हादसे अब हादसे नहीं रह गए हैं, यह अब रोजमर्रा की सामान्य बात हो गई है। मैं यह जानना चाहती हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ? क्या हमारे रेल मंत्रालय का नजरिया इन हादसों के प्रति निर्मम हो गया है ? क्या इन हादसों को वह बहुत ही उपेक्षित ढंग से नहीं ले रहे हैं ? उपसभाध्यक्ष महोदया, मुझे तो यह लगता है कि पिछले एक वर्ष से हमारी सरकार जिन नीतियों पर चल रही है और जिसके चलते यह कहा जा रहा है कि सरकार कोई धर्मशाला नहीं है, समाज कल्याण के कामों के प्रति सरकार का कोई दायित्व नहीं है।

...और चूंकि रेलवे की सुरक्षा समाज कल्याण के अन्तर्गत आती है, नागरिकों की सुविधायें समाज कल्याण से सम्बधित हैं और इसीलिये आई०एम०एफ० और वर्ल्ड बैंक के निर्देशों पर चलने वाली हमारी सरकार रेलवे सुरक्षा की ओर कतई ध्यान देना आवश्यक नहीं समझती। शायद उनके आकाओं से उनको ऐसा ही निर्देश मिला है अन्यथा क्या कारण है कि हमारी सरकार और हमारा रेलवे मंत्रालय लगातार इस तेज गति से रेल यात्रियों पर बोझ डाल रहा है, टिकटों का दाम लगातार बढ़ाया जा रहा है और बदले में सुविधाओं को आप देखें तो सुविधाओं की गति ठीक उल्टी दिशा में चल रही है ?

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज)** : सरला जी, आप अपना स्पष्टीकरण मंत्री जी के वक्तव्य तक सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** : मैं उनके वक्तव्य तक ही सीमित रख रही हूं। चूंकि, उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इसको बिल्कुल तकनीकी नहीं बनाना चाहती क्योंकि यह हमेशा का मामला है इसलिये मैं चाहती हूं कि थोड़ी गंभीरता में जाकर मंत्री जी इसका जवाब दें। महज तकनीकी मुद्दे उठाना मेरा मकसद नहीं है, इसलिये मैंने पहले ही कहा कि मैं सिर्फ तकनीकी मुद्दे उठाना नहीं चाहती।

तो, उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि रेलवे की व्यापक सुरक्षा का इन्तजाम करने के लिये क्या उनके पास कोई ठोस प्रारूप है या नहीं ? क्या वह किसी ठोस योजना पर बातचीत कर रहे हैं या नहीं ?

उपसभाध्यक्ष महोदया, जब यह घटना घटी, हालत यह है कि नागपुर के पास में यह घटना पांच बजे घटी और सात बजे नागपुर स्टेशन पर फोन करके पता लगाने की कोशिश की गई कि कौनसे डिब्बे पटरी से उतरे हैं तो नागपुर स्टेशन इस बात की जानकारी देने के लिये तैयार नहीं था। उसको मालूम तक नहीं था कि कौनसे डिब्बे रेलवे की पटरी से उतरे हैं। इतनी गफलत जहां चल रही हो, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्या होंगे ?

उपसभाध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने कहा है कि तोड़-फोड़ की घटना थी या ऐसा ही कुछ था। तो मैं यह जानना चाहती हूं कि आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि 10 तारीख को आप जांच शुरू कर रहे हैं और आज 17 तारीख है, क्या मंत्री महोदय के पास इस हफ्ते भर में कोई ऐसी प्रारंभिक जांच के संकेत मिल रहे हैं, जिनसे पता चले कि यह तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने वाले कौन थे ? कौनसे तत्व इन गतिविधियों में लिप्त थे ? ताकि सही चेहरे हमारे सामने आ सकें।

इसी के साथ, उपसभाध्यक्ष महोदया, (समय की घंटी) आपकी घंटी लगातार बजती जा रही है।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज)** : आपके बारे में पहली बार बजी है।

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** : इस हादसे में जो भी परिवार पीड़ित हुये हैं, उनको तुरन्त मुआवजा दिया जाना चाहिये और चिकित्सा की भी व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जानी चाहिये। वक्तव्य में हमारे पास जरूर आ जाता है कि यह व्यवस्था की जा रही है, लेकिन हकीकत में जाकर देखें तो पता चलता है कि उन तक कुछ नहीं पहुंचा। इसलिये मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय इस बात का भी यहां पर खुलासा कर दें कि रेलवे के जिन सुरक्षा नियमों के तहत आपको उनको मुआवजा देना है, वह उन तक पहुंचा है या नहीं ? धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Shri Gurudas Das Gupta, not present. Shri Bhubaneswar Kalita, not present. Shri N. Giri Prasad

SHRI N GIRI PRASAD (Andhra Pradesh) :' Madam Vice-Chairman, it is very unfortunate that a railway accident took place involving Ahmeda-bad-Howrah express train on the 9th July. This is not the first time that the Railway Minister is coming here and making statement. I had heard earlier also he has made statements when railway accidents took place in many parts of the country especially in South Central Railway section. Accidents took place due to sabotage and due to technical reasons. There were many reasons. I am afraid if this type of accidents go on taking place and every time the Minister comes here and makes a statement, it is not going to solve the problem. I want to know what steps the Railway Ministry is taking to prevent such accidents? May I know from the Minister whether this accident near Nagpur took place due to sabotage by some people? If so, who are those people? What steps the Railway Minister has taken to arrest the culprits involved in the sabotage because in those parts ...It is bordering our State also—there are some elements who are bent upon creating problems of this type. There was the burning of a railway bogie in which some 70 or 80 people were killed. There were some other accidents also of this type. The hon. Minister must be knowing about them because he also comes from the same State, When there are such problems, the Government and the Railway Ministry should take clear and concrete steps to solve them because the safety of passengers is involved. Of course, numerically, these accidents are not more nowadays. But non-maintenance or non-renewal of tracks, and non-maintenance of bogies and rolling stock create more problems. Also, the Government or the Railway Ministry has completely fai-ed to motivate the railway staff and about 70 per cent of the accidents take place because of their negligence, according to their reports. In such conditions, what are the steps the Railway Ministry is taking to motivate the staff to be conscious about the posible dangers or the accidents that are likely to take place so that preventive measures can be taken? I am afraid, the Railway Ministry is taking a complacent view of things comparing the number of accidents with the distance travelled, kilometre-journey or something like that, It should not be like that. Whether the number of accidents is increasing or not is not the criterion. The number of passengers killed or injured in such accidents is slowly increasing year by year_ I have personal knowledge of such accidents. Once I had to travel by a particular train. But, because of an accident involving some other train, there was some dislocation and I had to take to some other mode of transport. A lot of dislocations take place because of a railway accident. After every accident, the fear of an accident among passengers stays for one or two months. It takes one or two months for them to forget the accident. In this context, I would like to know from the Minister what steps he is going to take in the coming months or years to renew the assets like the rolling stock and tracks and to pre. vent sabotage by the elements who are bent upon doing that

I also understand that there is delay in payment of compensation by the Railways to the next of kin of the people killed in accidents or to the people who are injured in accidents. In some cases, it seems, the delay is inordinate. Why should the Railway Ministry take so many years or months to settle claims? They are aware of the people who are killed. It does not need any big evidence to prove the death. And local authorities like Collectors can be consulted, if necessary. On such consultation, they can pay the compensation. It is a simple affair For that, why should they take so many months or years?

I request the hon. Minister to consider all these problems and assure people that such accidents will not take place. I also hope that he would tell us what possible steps Will be taken by the Ministry to prevent such accidents and save the lives of people.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam Vice-Chairman, if we go through the statement of the hon. Minister, we find that in respect of the acident that took place between Badnera and Wardha junctions, prompt action was taken by Railway officials for immediate relief operations and the hon. Minister also visited that place. But, unfortunate in the Central Railway, the number of accdents is increasing year by year. The figure shows that the number of accidents during the last six months has increased as compared to the previous years. What is the reasons for it? According to the report that is available, this incident has taken place because the fishplates were found to have been removed and it appears to have been a clear case of sabotage. The hon. Minister in his statement stated that the sabotage has been predicted and an enquiry has been ordered. I would like to know from the hon. Minister whether any preliminary enquiry has been conducted. If so, what is the report of the preliminary enquiry?

According to the statement of the hon. Minister, about 14 persons lost their lives and another 20 sustained injuries. Out of these 20 persons, some have sustained serious injuries. I would like to know whether there was any more casualty out of these injured persons in spite of the medical aid that has been given to them. The Commissioner of Railway Safety has been ordered to hold an enquiry. The . Committee has been constituted on . 10th of July. What is the time-limit that has been given to the Commissioner of Railway Safety to submit 'the report so that further action can be taken in this regard Has any person been arrested for removing the fishplates? Above all one question remains. What are the reasons for such accidents? In the Central Rail-Way, as the hon. Member, Mr. Vithalbhai Patel, said, the bogies are old; creaking sound is there; the passengers amenities are not given and no proper care has been taken to maintain the bogies properly. As far as the Central Railway is concerned there are a lot of complaints about the management of the affairs of the Railways. Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what are the reasons for large number of accidents in that sector which have been increasing year by year. The hon. Minister has to answer this point.

As far as compensation is concerned, I am glad the hon. Minister has said that the amount of compensation payable in case of death and in case of injuries which deprive a person of all capacity to do any work is Rs. 2 lakhs. This amount will be given to their kith and kin. A sum of Rs. 1,80,000 will be given to those who have sustained serious injuries. *(Interruptions)*

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: The injured people have got only Rs. 5,000. *(Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): The Minister will reply.

SHRI V. NARAYANASAMY: If the persons who have sustained grievous injuries got only Rs. 5,000, then it is a serious matter. It should be increased suitably. The compensation of Rs. 2 lakhs which has been announced is not fixed amount. It is not an amount which has been gven to the passengers who were traveling in that train. The amount of compensation should be increased considerably. If those persons who have received grievous injuries have not been paid the compensation as men-

tioned by the hon. Minister in the statement, then that is a very serious matter. Every now and then, when an accident takes place, the hon. Members' demand is that the compensation should be increased. Therefore, it should be at least Rs. 3 lakhs for the kith and kin of those who have died and those who have received permanent disabilities, whose limbs have been amputated, they should be given at least Rs. 1,50,000 This should be the compensation amount which the Railways has to fix. In the past, whenever an accident took place, it was only when the Members demanded the increase that the compensation amount was increased. That should not be the case. Just like the air ways. They have to the compensation amount at a higer slab and they have to pay the amount. There should not be any delay in disbursing the amount to the victims

who suffered injuries and to the kith and kin of the persons who died in the accident.

**मौलाना अब्दुल्ला खान आजमी** (उत्तर प्रदेश) : शुक्रिया मैडम । आजकल जिस तरह से ट्रेनों के हादसात हो रहे हैं, उनके बारे में हुकूमत और पुलिस अफसरान की तरफ से अक्सर इस तरह का इजहार किया जाता रहा है कि यह आतंकवादियों द्वारा काम अंजाम किया जा रहा है और जिस तरह से यह ट्रेन दुर्घटना हुई है, जिसमें 14 आदमी मारे गये, 20 आदमी घायल हुये हैं, मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि घायल लोगों को अस्पताल ले जाने के लिये फौरन कार्रवाही न होने के कारण घायलों में भी कुछ लोग मरे हैं । इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं । सच्चाई क्या है, उनको ले जाने में क्यों हुई, इस बात का सरकार क्या जवाब दे रही हैं और उसकी सच्चाई क्या है ? दूसरी बात जो बहुत जरूरी है वह यह है कि ट्रेनों में भी आतंकवादियों ने लोगों को मारा है । कई बार आतंकवादी ट्रेनों पर हमला कर चुके हैं और कई बार आतंकवादियों ने पटरियों को उखाड़ा या ट्रेनों के जाने से पहले उनमें बम भी रखे । इस तरह उनमें बम ब्लास्ट भी हो सकता हैं । उन लोगों को इन हादसात से बचाने के लिये क्या तदबीर गवर्नमेंट लगा रही है या उनको रोकने के लिये क्या काम करने जा रही है । जहां वक्त से ट्रेनों को चलना है उनमें आतंकवादी बम रख सकते हैं, इससे बचाने के लिये और ट्रेनों की पटरियों की मुस्तकिल करने के लिये सरकार क्या कर रही है ? इसके लिये मुस्तकिल इंतजाम नहीं करेंगे तो ऐसे हादसात जिन के जरिए लोग मरे हैं उनको आप रोक नहीं पायेंगे । मैं जानना चाहता हू कि गवर्नमेंट के पास क्या तरकीब है इसके लिये । इसके साथ ही जो लोग मरे हैं, उनके लिये जैसा नारायणस्वामी जी ने मुतालबा किया है कि 3 लाख रुपया दिया जाय, वह दुरुस्त है, वह उनको दिया जाना चाहिये ।

**श्री मोहम्मद खलीलूर रहमान** (आंध्र प्रदेश) : मैडम, यह इंतहाई अफसोस की बात है कि पिछले 6 महीनों में जहां तक ट्रेनों के हादसात का सवाल है, दिन ब दिन इनमें इजाफा होता चला जा रहा है । हो सकता है इसमें सेबोटाज हो जैसा कि शुबहा किया गया है । जो वाकया 8 दिन पहले हुआ, कुछ तो इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई होगी, कुछ तो सामने आना चाहिए । अगर सेबोटाज है तो जो लोग इस तरह की हरकत किए हैं क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारी इन सात आठ दिनों में अमल में आई है यह मैं पूछना चाह रहा हूं । अगर सैबोटाज नहीं है तो यह देखिये कि क्या हमारी फिश प्लेटें, हमारी लाइनें इतनी कमजोर हो गई हैं कि हमारी फास्ट ट्रेन के काबिल हीं हैं कि बिना एक्सीडेंट के हमारी फास्ट ट्रेन उन पर चल सकें ? यह सेंट्रल रेलवे या वेस्टर्न रेलवे या सदर्न रेलवे का सवाल नहीं है । पूरी रेलवे इस किस्म की हो गई है, पूरी रेलवे में इतनी कमजोर ट्रैक्स डाली गई है । जरूरत इस बात की है कि इन ट्रैक्स को मजबूत बनाने की तरफ हमारी रेलवे मिनिस्ट्री और रेलवे विभाग तवज्जह दें ।

अभी दो तीन महीने पहले हमारे का प्राइवेट सेक्टर में जो एक्सीडेंट हुआ था वह एक्सीडेंट निहायत भयानक किस्म का था । मैं जानना चाहता हूं कि जो सैबोटाज की कोशिशें हैं उनको खत्म करने के लिये आप क्या कर रहे हैं ? क्या इनकी निगरानी कर रहे हैं, ट्रैक्स की निगरानी कर रहे हैं ताकि इस तरह की सैबोटाज करने वालों को इस किस्म का मौका न मिले ।

तीसरी चीज यह है कि आम तौर पर कंपेंसेशन बढ़ाने का मतालबा किया जा रहा है । वह बिल्कुल सही बात है कम्पेन्सेशन की । कम्पनसेशन एक्ट के मुताबिक तो मिलेगा ही । लेकिन इससे हटकर मैं पूछना चाहता हूं कि इमीडिएट रिलीफ के तौर पर आपने मरने वालों के नजदीकी को क्या दिया है जो घायल हुए हैं उनको क्या दिया है ? मैं यही जानना चाहता हूं । शुक्रिया ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): Madam Vic '-Chairman, it is really painful for me to address this august House on the occurrence of accidents parti-cularly this accident which has taken plans on 9th July. Hon. Member, Shri. J.P. Mathur, said that whatever inquiry had been ordered should be ind pendent of Railways. The Com-misiner of Railway Safety who cor lucts the inquiry is an indepen-derastatutory authority working under the Ministry of Civil Aviation. Of course, *prima facie* there was sa-bolago because of the removal of fish places. However, immediately on 10thJuly the Commissioner of Rail-way *Sa*fety started conducting the inquiry and he has almost finished it and ha has to submit his report. So, the question of preliminary inquiry does not arise now because the final inquiry which the Commissioner is to d*o* has been conducted.

Madam, another aspect is about the compensation. There were fourteen deaths. Hon. Member, Azmiji, asked about the number of persons died on the way to hospitals. None has died on the way to hospitals. Medical relief vans rushed to the spot immediately, apart from the local doctors who also came there. We had taken assistance from the nearby military camps so much so that all the injured persons were immediately removed to Sevagram Hospital and other hospitals and I have seen them personally. Later on one person died; that is how the total number of the dead has come to 15.

Madam, as per our Act, ex-gratia is paid to the relatives of the dead and the injured also; for the dead Rs. 10,000 are paid, for grievous in juries Rs, 2,500 and for trivial in juries Rs. 1,000. This does not cover the compensation. Compensation is really a factor ______

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Were the victims of Karnataka Express paid Rs. 10,000? You have not paid them.

SHRI MALLIKARJUN: Kindly permit me. So far as compensation is concerned, proper claim has to be filed before the Tribunal and naturally in some cases it may be difficult also because no lawyer may be coming forward. Even if a lawyer comes forward he may take a share of the compensation which the victim gets. So, this is the laid down procedure. Earlier it was taking a lot of time because the Court had to nominate a judge to dispose of the cases. Now, we have our own Tribunal and the processing of compensation cases has been hastened. Railway authorities immediately in-form the relatives and friends of all the dead and injured people so much-so that they can take care of certain things. So far as the hon. Member's question regarding payment of com-pensation to the victims of Karnataka Express is concerned, I cannot say anything unless a claim petition is filed before the Tribunal; then only

[Shri Mallikarjun]!

the compensation will be paid.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: The poor lady had got to pay Rs-20,000 to her lawyer. Why don't you provide her a lawyer?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ); Have you got any knowledge of this fact?

SHRI MALLIKARJUN: Madam, this is not in my knowledge. For the first time this has come to my knowledge. I will see what best can be done.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: She had been to Shri Jaffer Sharief also. But nothing has happened so far. Why are you misleading the House?

SHRI MALLIKARJUN: I am not misleading the House. Kindly bear with me.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: She has not got even a single paise.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): The hon. Member is stating it on the floor of the House. You don't have any knowledge of the fact...

SHRI MALLIKARJUN; I am not misleading the House. Let there not be any misunderstanding.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): You gather the information and supply it to him.

SHRI MALLIKARJUN: That is what I am saying.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): The Minister has) no knowledge of the fact.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Three MPs have written letters.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ); But letters must not have reached him. They must have reached Mr. Jaffer Sharief. Mr. Minister, you gather the information on this and supply it to him.

SHRI MALLIKARJUN: Certainly. Since i; has come to my knowledge, I will see what can be done.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): You must gather the facts and supply the facts to him.

SHRI MALLIKARJUN: Yes. This is about compensation. One hon. Member: has asked about amputation. If amputation has taken place, its range is from Rs. 16,000 to Rs. 1,30,000. According to the ca-pablity of the victim it will be decided by the Tribunal. So far as rolling stock is concernd, it is true that in Indian Railways there are some overaged coaches. We are still re« pairing them and trying to use them. More than 5000 coaches are like that We have planned to replace them. Apart from that we regularly attend to the maintenance of the rolling stock, whether a locomotive or a coach or a wagon.

SHRI V. NARAYANASAMY: In the Central Railway accidents are more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): He is still replying. He has not finished his reply.

SHRI MALLIKARJUN: In the Central Railway, I can say, in some years there are more cases of accidents and in some years less number of accidents. If you want, I can give you the data. In 1990-91, there were 41 accidents due to the railway staff failure in Central Railway. In 1991-92 there are 35 cases of acc'dents. But on the contrary because of the failure of the mecha-

nical equipments, in 1990, there were 2 accidents and in 1991-92 there were 8 accidents. Madam, accidents are normally occurring because of equipment failure and also because of human failure and sometimes due to the railway staff and other lapses.

Madam, the measures which we are taking are equally important, like, we are taking intensive inspec tion of stations, cabins, level cros sings, signalling and telecom- gears, maintenance of depots, coaches wa gons and locomotives, extensives, counselling and training of staff of various departments with special re ference to safe running of trains, proper maintenance of assets inten sive monitoring of the working of sensitive categories of staff such as drivers, station masters, surprises checks against carrage of inflamable and explosive material in passenger trains, inspection of different Zonal Railways by two-level Central safety teams from the Railway Board, con tributing emphasis on renewal and rehabilitation of overaged assets particularly track bridges, rolling-stock. Madam, in the Eighth Plan period we have allocated Rs. 4500 crores for the renewal of tracks. It is not fair to say that the Railways do not pay attention to the tracks because the whole engineering sys tem devotes its time to the proper maintenance of the tracks which is essentially required. Regularly, permanent way inspector moves on it key-man moves on it. They check up if there is any flaw in the tracks, whether fish-plates or nut-bolts and apart from that .....

*(Interruptions)*

श्री राम नरेश यादव : ट्रेक सुरक्षा के लिये क्या कदम उठा रहे हैं ?

Regularly the condition of the track is found out by using certain machinery. The machinery helps to find out fractures in the tracks, so much so that we can avoid derail-ment *of* trains.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Regarding safety of railway tracks, he wants to know what measures are being taken.

SHRI MALLIKARJUN: The Rail way tracks are regularly patrolled by the permanent way inspector, key-men etc. For example, in the sensitive areas like Punjab, about 5000 people patrol the tracks regular ly. So this is a regular continuous process It is not that the railways become conscious of it only after an accident takes place. The railways are conscious of maintaing the tracks properly. For that reason regular patrolling is done. They check up everything. This accident actually occurred within half-an-hour. Ear lier, before the occurence of this accident a goods train had passed from there. The sabotage took place within half-an-hour. Within half-an-hour the fishplates were re. moved. Apart from this certain other measures are taken like track circuiting, inter-locking, level cros sing, auxiliary warning system and so on and so forth. Apart from that we have a high-level safety team which checks certain things like correct procedure for reception and dispatch of trains, correct observation of rules in automatic signalling, safety ma rshalling of coaches, safety precaution at level-cros-sing, visibility of signals, regular carriage and wagon examination, manning and safe handling of locos, maintenance of points and crossings, including emergency crossings. So all these measures are being taken. In spite of all these measures accidents occur due to various reasons. Most of the accidents take place be-cause of human failure. Accidents because of human failure are more than 50 per cent and because of equipment falure 28 per cent. There are track and other failures also. Apart from these, there are certain things which are not within the cont-

[Shri Mallikarjun]

rol of the railways. Accidents which take place at level-crossings is an example. The users have to be a little careful but instead they rush and collide. We have given strict instructions to all the General Managers to be safety-conscious and see that accidents are reduced and also to see to the safety and security of the passengers and to see that proper amenities are provided to them. Thank you.

## ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): I have to make an announcement. I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held on the 17th July, 1992, allotted time for Government Legislaitve Business as follows:

| Business | Time Allotted |
|---|---|
| 1. Consideration and passing of following Bills: | |
| (a) The Coal Mines (Nationali-sation) Amendment Bill, 1992 | 24 Hours |
| (b) The Beedi and Cigar Workers (Condition of Employment) Amendment Bill, 1990 | $1^{1/2}$ Hours |
| 2. Consideration and passing of the Bhopal Gas Leak Disaster (Pro cessing of claims) Amendment Bill, 1992, after it is passed by Lok Sabha | 4 hours |

Now we will take up special mentions .

मेरे पास कुछ स्पेशल मेंशंस हैं । अगर आप चाहें तो इनको हम खत्म करें । दो-तीन हैं, आप चाहते हैं तो इनको खत्म करें ।

कई माननीय सदस्य : मन्डे को ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अगर सदन की सहमति है, तो ठीक है ।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 20-7-92, प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

The House adjourned at forty eight minutes past five of the clock till eleven of of the clock on Monday, the 20th July 1992